भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2926

18.03.2025 को उत्तर के लिए नियत

पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

2926. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या भारी **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमई-ड्राइव योजना के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई और इसके अंतर्गत कितनी राशि का उपयोग किया गया है;
(ख) क्या महाराष्ट्र में चार्जिंग अवसंरचना के विकास के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं ;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) महाराष्ट्र में उक्त योजना के अंतर्गत कितनी ई-बसें और ई-ट्रक संचालित किए जा रहे हैं ;और
(ङ) तत्संबंधी जिलावार ब्योरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) : भारत सरकार ने 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 29.09.2024 को पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम को अधिसूचित किया है। यह स्कीम 31.03.2026 तक उपलब्ध है। 01.04.2024 से 30.09.2024 तक लागू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस)-2024 को पीएम ई-ड्राइव स्कीम में आमेलित कर दिया गया है। पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए वित्तीय प्रोत्साहन मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के उपभोक्ताओं (खरीदारों/अंत प्रयोक्ताओं) को प्रदान किया जाता है, न कि सीधे राज्य सरकारों को। ये प्रोत्साहन इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में होते हैं। इसके बाद केन्द्र सरकार मूल उपकरण विनिर्माताओं को इस प्रोत्साहन राशि की प्रतिपूर्ति करती है। महाराष्ट्र राज्य में 01.04.2024 से 12.03.2025 तक पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत बेचे गए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या इस प्रकार है:

खंड	ई-दुपहिया	ई-तिपहिया (ई-रिक्शा)	ई-तिपहिया (एल5)	कुल
बिके इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या	1,59,446	10	6,233	1,65,689

(ख) और (ग) : महाराष्ट्र राज्य सहित अखिल भारतीय आधार पर सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए पीएम ई-ड्राइव स्कीम में 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

(घ) और (ङ) : पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए 4,391 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रारंभ में, इस स्कीम के अंतर्गत 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ शहरों अर्थात् मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत और पुणे को लक्षित किया गया है। पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत अब तक कोई इलेक्ट्रिक बस तैनात नहीं की गई है।

पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत ई-ट्रक और अन्य उभरते इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए कुल 500 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के तहत अब तक किसी भी ई-ट्रक के लिए आर्थिक प्रोत्साहन नहीं दिया गया है।

******